

स्वास्थ्य चेतना यात्रा 2009 के शुभारम्भ

के अवसर पर

माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री महोदय,

के उद्बोधन

का प्रारूप

स्थान:— महर्षि गौतम विद्यापीठ,
चौथा माइल स्टोन,
वाटिका रोड़

दिनांक:— 15, सितम्बर 2009

माननीय मुख्यमंत्री, श्री अशोक गहलोत जी, केन्द्रीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री आलि जनाब गुलाम नबी आजाद साहब, गृहमंत्री श्री शांति धारीवाल जी, संसदीय सचिव श्री दिलीप चौधरी जी, श्रीमती गंगादेवी, श्री मकबूल मंडेलिया जी, ग्रामीण स्वास्थ्य चेतना यात्रा के शुभारम्भ अवसर पर आयोजित इस राज्य स्तरीय समारोह में उपस्थित जनप्रतिनिधिगण, मीडिया से आये बंधु एवं भाईयों-बहिनों ।

रोगी इन्सान की खिदमत को खुदा की सबसे बड़ी इबादत मानते हुए लोगों को समय पर समुचित एवं गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध कराने के लिए वर्तमान सरकार ने अपने प्रयासों में कोई कसर नहीं छोड़ रखी है। हमारी सरकार ने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य की महत्ता को समझते हुए सत्ता में आते ही वर्ष 2009-10 के बजट में चिकित्सा राजस्व व्यय मद् में दो हजार पॉच सौ छियालिस (2546) करोड़ रुपये का प्रावधान रखा है, इससे यह साफ जाहिर है कि राज्य सरकार दूरदर्शन माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में चिकित्सा सेवाओं के विस्तार के प्रति संवेदनशील है ।

स्वास्थ्य विभाग द्वारा संचालित योजनाओं एवं कार्यक्रमों की जानकारी आमजन को उपलब्ध कराने के साथ प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर चिकित्सा शिविर आयोजित कर निःशुल्क जॉच एवं उपचार की व्यवस्था के लिए प्रदेशभर में आज से एक माह तक आयोजित की जाने वाली स्वास्थ्य चेतना यात्रा का शुभारम्भ किया जा रहा है । स्वास्थ्य चेतना यात्रा में स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं जैसे- कुपोषण, मलेरिया, एड्स, संक्रामक रोगों आदि के बचाव एवं उपचार के बारे में जानकारी के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से सामान्य जनता को स्वस्थ रहने के संदेश दिया जायेगा । इन शिविरों के माध्यम से स्वास्थ्य विभाग गाँव-ढाणी में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति तक पहुँचने का प्रयास करेगा ।

ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर स्वास्थ्य सेवाएँ मुहैया कराने व स्वास्थ्य सेवाओं के बुनियादी ढाँचे में गुणवत्तापूर्ण बदलाव लाने के उद्देश्य से केन्द्र सरकार ने ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की स्थापना की थी। मैं इस मौके पर केन्द्र सरकार और माननीय केन्द्रीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ जिन्होंने

इस मिशन के अन्तर्गत इस वित्तीय वर्ष में हमें 1010 करोड़ रुपये का वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाई है। इसके तहत अब तक हमने तीन सौ तिहेतर करोड़ रुपये व्यय भी कर लिये हैं। इसके साथ ही आज ही नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम की राष्ट्रीय शुरुआत के लिए राजस्थान का चयन कर प्रदेश का गौरव बढ़ाया है। हम केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी को यह विश्वास दिलाते हैं कि केन्द्रीय स्वास्थ्य योजनाओं की पूर्ण क्रियान्वित में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे।

राज्य में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की शुरुआत 1999 में माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी, के पूर्व कार्यकाल के दौरान "मुख्यमंत्री जीवन रक्षा कोष" का गठन कर की गई थी। वर्तमान में 1 जनवरी 2009 से इस योजना को व्यापक रूप देते हुए इसे मुख्यमंत्री बी.पी.एल. जीवन रक्षा कोष का नाम दिया गया है जिसमें बी.पी.एल. मरीजों को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों से लेकर मेडिकल कॉलेज से सम्बद्ध अस्पतालों तक निःशुल्क चिकित्सा का लाभ प्रदान किया जा रहा है। राज्य में रोग संबंधी उपचार एवं निदान की सुविधा नहीं होने पर राज्य के बाहर अखिल भारती आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली एवं स्नातकोत्तर शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान चण्डीगढ़ में भी भेजने की व्यवस्था की गई है। योजना के तहत अब तक 10 लाख 22 हजार आठ सौ अट्ठावन रोगियों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा प्रदान की गई इस पर 14 करोड़ 32 लाख रुपये खर्च किये गये।

मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में कमी किये जाने के उद्देश्य से संस्थागत प्रसव को प्रोत्साहित करने के लिए जननी सुरक्षा योजना के तहत राज्य में अब तक 23 लाख 70 हजार पाँच सौ छियासी महिलाओं को लाभान्वित कर करीब तीन सौ तिहरेपन करोड़ 44 लाख रुपये की राशि व्यय की गई। राज्य सरकार द्वारा बी.पी.एल. परिवार की प्रसूताओं को प्रथम प्रसव पर मुफ्त उपहार योजना के तहत 5 लीटर देशी घी भी दिया जा रहा है।

शिशु स्वास्थ्य सेवाओं में गुणात्मक सुधार के लिए सभी जिला अस्पतालों में नवजात शिशु देखभाल इकाई को प्रियदर्शनी योजना के तहत प्रभावी कर क्रियाशील किया जा रहा है। बच्चों को जानलेवा बीमारियों से बचाने के लिए नियमित टीकाकरण कार्यक्रम के तहत गत वर्ष 11 करोड़ 13 लाख 31 हजार रुपये व्यय किये जाकर 1 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई गई तथा डी.पी.टी., बी.सी.जी. एवं खसरे के टीके लगाये गये हैं। इस वर्ष अब तक इस कार्यक्रम पर 1 करोड़ 61 लाख रुपये व्यय किये जा चुके हैं।

प्रदेश के दूर-दराज के ग्रामीण क्षेत्र जहां चिकित्सा सेवाएँ उपलब्ध नहीं हैं उन लोगों को स्वास्थ्य सेवाएँ उनके घर तक पहुँचाने के उद्देश्य से "राजीव गाँधी ग्रामीण चल चिकित्सा इकाई" स्थापित की गई है। योजना के तहत प्रत्येक इकाई के अन्तर्गत दो वाहन निर्धारित किये गये हैं जिनमें एक वाहन चिकित्सा दल के लिए तथा दूसरे वाहन में सभी जॉच उपकरण एवं दवाईयों उपलब्ध होती है। योजना के तहत मासिक आधार पर ग्रामीण क्षेत्रों में शिविर आयोजित कर स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध कराई जा रही हैं।

प्रदेश की जनता को आपातकालीन सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से 108 आपातकालीन एम्बुलेंस सेवा संचालित की जा रही है। इस योजना के तहत राज्य में इस तरह की एक सौ चौसट एम्बुलेंस सेवाएँ संचालित हैं जो सूचना मिलने के 25 से 45 मिनट के अन्दर रोगी को अस्पताल पहुँचा देती हैं। यह आमजनता के लिए पूर्णतः निःशुल्क है।

ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधा मुहैया कराने के लिए राज्य में इस वर्ष पॉच सौ सैंतीस उपस्वास्थ्य केन्द्र खोले जायेंगे। राज्य में आधारभूत सुविधाओं के विस्तार के तहत इस वर्ष 205 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर प्रसूति कक्षों का निर्माण, 100 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर अतिरिक्त प्रसूति वार्डों का निर्माण तथा 50 भवन रहित उप स्वास्थ्य केन्द्रों के भवनों का निर्माण किये जाने के साथ चिकित्सालय में

चिकित्सकों एवं नर्सों के ठहराव को सुनिश्चित करने के लिए 32 चिकित्सा संस्थानों पर आवासीय भवनों का निर्माण किया जायेगा ।

विकास एक सतत् प्रक्रिया है और हमारा यह संकल्प है कि हम स्वस्थ प्रदेश की कल्याण को साकार करने की दिशा में कोई कोर-कसर बाकी नहीं रखेंगे । मैं इस मौके पर एक बार फिर केन्द्रीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री गुलाम नबी जी आजाद और माननीय मुख्यमंत्री जी का तहेदिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने इस पुनीत अवसर पर पधार कर हमारी हौसला अफजाई की ।

जयहिन्द !